Nationalisation of Foreign Drugs Companies

+

*3. SHRI TRIDIB CHAUDHURI:
SHRI HARGOVIND VERMA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILI- be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published in the 'Business Standard' of Calcutta on January 24, 1978 to the effect that Government have come to a firm view that there would be no nationalisation of foreign drug companies as recommended by the Hathi Committee and FERA curbs with regard to dilution of foreign equity holdings would not apply to these companies;

(b) if so, their reaction to the news item; and

(c) whether Government have finalised their consideration of the Hathi Committee Report and come to any final decision about its recommendations?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). हाथी समिति की सारी सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं और इन पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने की संभावना है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा : हाथी समिति की जो रिपोर्ट आई है, उस के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण को खत्म करने की बात हुई है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने जो समिति बनाई थी, क्या यह सरकार उसी के आधार पर काम करेगी, या वह कोई दूसरी समिति बना कर और फिर से जांच कर के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करेगी ।

श्री जनेश्वर मिश्र : हाथी समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के विचाराधीन है । मैं नहीं समझता कि कोई और समिति इस के लिए बनाई जायेगी । जब यह सवाल कैबिनेट के विचाराधीन था, तो उस की तरफ से एक उपसमिति बनाई गई थी । उस उप समिति ने भी एक तरह से निर्णय ले लिया है, और उस की रिपोर्ट तथा निर्णय पूरी कैबिनेट के सामने जायेगा ।

श्री हरगोविंद वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर राष्ट्रीयकरण विदेशी कम्पनियों का नहीं होगा तो जो आप की देशी कम्पनियां हैं वे उन के मुकाबिले में प्रगति कर सकेंगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा विदेशी कम्पनियों का या होगा । अपनी तरफ से वह यह जोड़ रहे हैं ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, the Hathi Committee Report on p. 96 clearly states:

"The multi-national units operating in India produce only a small fraction of bulk drugs. The main thrust of the multi-national units continues to be towards capitalising on drug formulations and non-drug items, like, cosmetics and luxury goods....The permission letters and COB licences have further helped these units to build enormous assets which are completely out of proportion to their investments....

The selective attitudes of multinationals even in the fields of research development are dictated almost entirely by their philosophy of global trade.

We are convinced that their continued presence in this country is a powerful damper on the challenge of our achieving the technological

goals of self sufficiency and self reliance.

Basic drugs are produced in the Indian sector including the public sector to the extent of about 90 per cent in tonnage terms and this demonstrates effectively the competence that has already been achieved in indigenous technical skills.

Continued presence in this country of the highly profit motivated multi-national sector can but promote only the business interest of this sector. Their presence in India as a part of their global effort to capitalise on human suffering in an organised manner must, therefore, cease as early as possible.

We, therefore, strongly recommend that the multi-national units in the field of drugs and pharmaceuticals should be taken over by Government and managed by the proposed National Drug Authority.'

In the context of this specific and clear pointer and a recommendation of the Hathi Committee, how is it that the Government has not nationalised or taken over the foreign drug houses in the country? I want a specific answer to this.

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि सरकार के विचाराधीन हाथी कमेटी की रिपोर्ट है और बहुत ही जल्दी निर्णय होने जा रहा है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order. This Report was submitted to the Government in April, 1975. How many more years do they want?

श्री जनेश्वर मिश्र : हाथी कमेटी की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है और माननीय सदस्य ने जिस सिफारिश का उल्लेख किया है उस पर भी विचार हो रहा है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I do not beat about the bush. I have quoted the Hathi Committee's Report.

MR. SPEAKER: He says, it is still under consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It was submitted to the Government in April, 1975.

MR. SPEAKER: You can censure them for that.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि सन 75 से हाथी कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है, अब तक उस पर विचार चल रहा है और देश का करोड़ों रुपया हर वर्ष मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा देश से बाहर निकला चला जा रहा है? नेशनलाइजेशन के बारे में जो आप सोचेंगे वह तो है ही लेकिन एक डेफिनिट बताइए कि हाथी कमेटी की रिपोर्ट पर आप कब तक विचार कर लेंगे और क्या इन मल्टी नेशनल ड्रग्स कम्पनियों का भारतीयकरण करने की दिशा में आप का विचार है या नहीं?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने पहले ही बता दिया अध्यक्ष महोदय, कि इस पर बहुत जल्दी विचार करेंगे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बहुत जल्दी का क्या सवाल है? सन 75 से मैं सुन रहा हूं कि बहुत जल्दी विचार किया जाएगा। सन 75 से सरकार का यही जवाब आता है कि बहुत जल्दी विचार करेंगे।

PROF. P. G. MAVALANKAR: Mr. Janeshwar Mishra, the Minister of State, might perhaps recall that his senior colleague, Shri Bahuguna, in the very last session of Parliament, that is, in December, 1977, very emphatically and categorically assured this House that the matter regarding the Hathi Committee's recommendations was absolutely on the table of

the Cabinet, that it was very hot and that, any minute, the decision would be taken. Therefore, he cannot give the information to the House in this way. I want to know what are the factors responsible between the date of Shri Bahuguna's answer and today, although more than two months have passed, which have delayed the Cabinet Sub-Committee and the Cabinet in coming to a decision which I should have thought for the Janata Party was clear and categorical, namely, the nationalisation of foreign drug houses. There is a tremendous thrust on and a deep drain of the resources of our country. When Mr. Janeshwar Mishra was on the Opposition Benches, he used to shout loudly about it. Therefore, I want to know what are the concrete and specific factors or obstacles or hindrances which are weighing with the Government to come to a decision this way or that way.

श्री जनेश्वर मिश्र : उसमें कोई ग्राब्स्टेकिल नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि केबिनेट की ग्रोर से एक उप-समिति बना दी गई थी जिसके ग्रध्यक्ष बाबू जगजीवन राम जी थे तथा स्वास्थ्य मंत्री, बहुगुणा जी श्री एच० एम० पटेल तथा श्री जार्ज फर्नांडिस सदस्य थे—उस कमेटी ने ग्रपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है ग्रौर पूरी केबिनेट के सामने विचार के लिए वह जा रही है। मैं समझता हूं यह कार्य शीघ्रता से हो रहा है।

श्री कल्याण जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, हाथी समिति की रिपोर्ट के बारे में सरकार का हमेशा यह ग्राश्वासन रहा है कि जल्दी से निर्णय लिया जाएगा। मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं तथा जानकारी चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि दवाई के बिजनेश में केवल दवाई नहीं बेची जाती है, कम्पनी का नाम बेचा जाता है ग्रौर हाथी समिति ने सिफारिश की है कि दवाई का जेनरिक नाम होना चाहिए—इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है या नहीं ? लगता है किसी को जानकारी नहीं है कि एक दवाई जो बनाई जाती है ग्रौर मल्टी नेशनल कम्पनी के द्वारा बेची जाती है वही दवाई हिन्दुस्तान की कम्पनी के द्वारा रुपए में चार ग्राने में बेची जाती है। वही क्लोरोक्वीन यहां सौ रुपए की एक हजार बेची जाती है। हाथी समिति ने सिफारिश की है कि दवाई का जेनरिक नाम होना चाहिए ग्रौर इस सिफारिश को लागू करने के लिए पहले भी सदन में ग्राश्वासन दिया गया कि इस पर जल्दी से निर्णय लिया जाएगा। ग्राज तमाम सदस्यों की इच्छा है ग्रौर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया गया है कि दवाई की कीमत बहुत महंगी है तो क्या सरकार दवाई के जेनरिक नाम रखने के बारे में निर्णय लेने के लिए तैयार है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने पहले ही बताया कि हाथी कमेटी की सारी सिफारिशों के बारे में शीघ्रता से विचार हो रहा है।

MR. SPEAKER: Next question.

SHRIMATI CHANDRAVATI: This is a very important question.

MR. SPEAKER: Next question.

Doubling of Bongaon-Sealdah Section of Eastern Railway

*4. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) at what stage does the project of doubling the Bongaon-Sealdah Section of the Eastern Railway rest now;

(b) whether it has been included in the Annual Plan for the year 1978-79; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) The survey conducted for doubling of